



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2012/माघ 21, 1933
No. 37]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2012/MAGHA 21, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2012

निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई हेतु सेस्टेट द्वारा वापस भेजा गया मामला

विषय : स्विट्जरलैंड और चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामीटेड के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच ।

सं. 14/11/2005-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति-निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

मामले की पृष्ठभूमि :

- (1) मै. निकोलस पिरामल इंडिया लि. (एन पी आई एल) ने उपर्युक्त अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत स्विट्जरलैंड और चीन जन.गण. (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामीटेड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया था ।
- (2) संबद्ध जांच में शामिल उत्पाद विटामिन-ए पामीटेड है। विटामिन-ए पामीटेड का विनिर्माण विभिन्न क्षमताओं और रूपों में किया जाता है और इन ग्रेडों की तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता के कारण सभी सांद्रणों और रूपों के विटामिन-ए पामीटेड को विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया था ।
- (3) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में 23 मार्च, 2006 को अधिसूचना सं. 14/11/2005-डीजीएडी के तहत पाटनरोधी जांच शुरू की । उक्त जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2004 से 30 सितम्बर, 2005 तक तथा क्षति अवधि 2000-01 से 2003-04 तक की थी ।

- (4) जांच शुरूआत की सूचना के उत्तर में आवेदक सहित हितबद्ध पक्षकारों ने सेस्टेट के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में उत्तर दायर किए और लिखित अनुरोध भी किए ।
- (5) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम शुल्क की सिफारिश करते हुए 20 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. 14/11/2005-डी जी ए डी के तहत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए और राजस्व विभाग ने 28 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. 47/2007-सी.शु. के तहत अनंतिम शुल्क लगाया था ।
- (6) मै. डी एस एम न्यूट्रीशनल्स प्रोडक्ट लि. (डी एन पी) ने प्रारंभिक जांच परिणामों पर विस्तृत टिप्पणियां दायर की जिनमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर क्षति मापदंडों की जांच से स्पष्टतः क्षति के पूर्ण अभाव का पता चलता है । क्षति रहित कीमत के निर्धारण को भी इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि औषध कीमत नियंत्रण आदेश (डी पी सी ओ) के अंतर्गत कानून में अधिकतम कीमत तय की गई थी और इसलिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण ऐसी कीमत पर ध्यान दिए बिना नहीं किया जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग ने डी पी सी ओ के अंतर्गत निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर अपने उत्पाद की बिक्री नहीं की होगी ।
- (7) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क की सिफारिश करते हुए 14 सितंबर, 2007 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए और राजस्व विभाग ने 30 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. 112/2007-सी.शु. के तहत निश्चयात्मक शुल्क लागू किया । निश्चयात्मक शुल्क 28.3.2007 अर्थात अनंतिम शुल्क लागू किए जाने की तारीख से लागू किया गया था ।
- (8) प्राधिकारी द्वारा 14 सितंबर, 2007 को जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों और राजस्व विभाग द्वारा 30 सितंबर, 2007 की अधिसूचना सं. 112/2007-सी.शु. के तहत जारी की गई सी.शु. अधिसूचना से असंतुष्ट होकर मै. डी एस एम न्यूट्रीशनल्स प्रोडक्ट लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय स्विट्जरलैंड में है, ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1995 की धारा 9(ग) के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) नई दिल्ली के समक्ष एक अपील दायर की।
- (9) माननीय सेस्टेट, नई दिल्ली ने 11.8.2011 के अपने आदेश द्वारा उक्त याचिका का निपटान किया । उक्त आदेश का प्रचालनात्मक भाग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार है :

“15.तदनुसार हम आवेदकों को निर्णयोपरांत सुनवाई का अवसर देने और अंतिम जांच परिणाम में ऐसे उपांतरण करने जिन्हें ऐसे निर्णयोपरांत सुनवाई के परिणामस्वरूप आवश्यक समझा जाए, करने के लिए ये अपीलें निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजने की अनुमति देते हैं । प्रतिवादी घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, यदि कोई हो, को भी ऐसे निर्णयोपरांत सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। अंतिम जांच परिणाम में किए गए किसी उपांतरण पर पाटनरोधी शुल्क लगाने वाली आक्षेपित अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर सरकार द्वारा उन्हें प्रभावी बनाते हुए विचार किया जाएगा । यह

प्रक्रिया इस आदेश की तारीख से 6 माह के भीतर पूरी की जाएगी और इस बीच यथास्थिति बनाए रखी जाएगी । चूंकि हम इन अपीलों की अनुमति वापस भेजकर प्रदान कर रहे हैं, इसलिए संबंधित स्थगन याचिकाएं, एम ए तथा सी ओ को निपटाया गया माना जाएगा । ”

(10) सेस्टेट के उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए और कानून एवं सिद्धांत के मामलों में माननीय सेस्टेट के 11 अगस्त, 2011 के उक्त आदेशों को चुनौती देने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकार के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के लिए निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई 13 दिसंबर, 2011 को आयोजित की ।

(11) माननीय सेस्टेट के 11 अगस्त, 2011 के आदेशों के अनुपालन में प्राधिकारी द्वारा आयोजित निर्णयोपरांत सुनवाई के अनुसरण में प्राधिकारी की कार्रवाई के अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है और प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम के संबंधित खंडों में विचार किया है ।

(12) *** चिन्ह इस प्रकटन विवरण में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

(13) जिन हितबद्ध पक्षकारों ने निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, उनके द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

(14) निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने प्राधिकारी द्वारा 13 दिसंबर, 2011 को आयोजित निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई में भाग लिया और मौखिक अनुरोध किया :

(क) मै. निकोलस पिरामल इंडिया लि. (एन पी आई एल)

(ख) मै. डी एस एम न्यूट्रीशनल्स प्रोडक्ट लि. (डी एन पी)

(15) निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित में किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

क. मै. डी एस एम न्यूट्रीशनल्स प्रोडक्ट लि. के अनुरोध

घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के बारे में अनुरोध

- i. निकोलस पिरामल घरेलू उद्योग नहीं है क्योंकि उसने सिट्रल रूट से विनिर्माण से धीरे-धीरे हटकर विटामिन ए एसोटेट 2.8 एम आई यू /ग्राम की मात्र खरीद पामीटेड 1.7 एम आई यू/ग्राम में परिवर्तन करने के एकल चरण हेतु शुरू कर दी । सुनवाई के दौरान निकोलस

पिरामल के काउंसिल ने यह अनुरोध किया कि कंपनी ने कम से कम दिसंबर, 2010 से विटामिन ए पामीटेट का उत्पादन मूल चरण से बंद कर दिया है और वे इस समय केवल विटामिन ए एसीटेट का परिवर्तन विटामिन ए पामीटेट में करने हेतु कार्यकलाप ही कर रहे हैं ।

- ii. विटामिन ए के दोनों रूप समान वस्तुएं हैं । विटामिन ए पामीटेट और विटामिन ए एसीटेट का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है और ये मात्र विटामिन ए के उप प्रकार हैं । विटामिन ए के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में परिवर्तित किए जाने के कार्य से निकोलस पिरामल घरेलू उद्योग नहीं बन जाएगा ।
- iii. चूंकि पिरामल अब घरेलू उद्योग नहीं है, इसलिए इस कार्रवाई में उसकी भागीदारी का अधिकार भी नहीं रह जाता है । पिरामल के विनिर्माण कार्यकलापों की प्रकृति से संबंधित वास्तविक अनुरोध भी भ्रामक हैं । तथाकथित "भिन्न उत्पादन प्रक्रिया" विटामिन ए एसीटेट से विटामिन ए पामीटेट में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है । परिवर्तन ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे विनिर्माण या उत्पादन माना जा सके ।
- iv. मात्र यह तथ्य कि ऐसे कार्यकलाप पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था, उसके विनिर्माण या उत्पादन का द्योतक नहीं है । उत्पाद शुल्क का भुगतान विटामिनों को शामिल करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के अध्याय-32 की टिप्पणी-10 के कारण किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि विपणन योग्य उत्पाद बनाने के लिए पैकिंग, पुनः पैकिंग, पुनः लेबलिंग अथवा कोई प्रक्रिया करना विनिर्माण माना जाएगा ।

गोपनीयता से संबंधित अनुरोध

- i. डी एस एम को न तो पाटन मार्जिन और न ही क्षति मार्जिन की गणना का प्रकटन किया गया है ।
- ii. प्राधिकारी पाटन एवं क्षति मार्जिनों की गोपनीय गणनाओं का प्रकटन करने में विफल रहे हैं । पाटन मार्जिन अनन्य रूप से निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित है और इसलिए उसे उपलब्ध कराना चाहिए था । इसी प्रकार अंतिम क्षति संबंधी गणना डी पी सी ओ कीमतों पर आधारित है जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है ।

निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से संबंधित अनुरोध

- i. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का गलत निर्धारण किया है । ऐसी स्थिति में जहां कोई बिक्री नहीं होती है अथवा बाजार विशेष की स्थिति या निर्यातक देश के घरेलू बाजार में कम बिक्री होती है तो ऐसी बिक्रियों की वजह से उचित तुलना नहीं हो सकती, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश की निर्यात कीमत के आधार पर करना होता

- है। बी एस एम का अनुरोध है कि स्विट्जरलैंड में बिक्री उक्त कंपनी द्वारा संबद्ध वस्तु की कुल बिक्री से 2% से कम है और इसलिए यह सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्रतिनिधिक नहीं है। सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उचित बाजार यूरोपी संघ है न कि स्विट्जरलैंड
- ii. आयातों से इतर कई कारकों अर्थात् सीमाशुल्क में कमी, रूपए की मजबूती आदि के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। यह क्षति सरकार द्वारा संगत अवधि के दौरान निर्धारित डी पी सी ओ कीमत के कारण भी हुई है जिससे घरेलू उद्योग अपनी कीमत नहीं बढ़ा सके।
 - iii. क्षमता उपयोग सभी उत्पादों के लिए दिया गया है न कि संबद्ध वस्तु के लिए और इसी वजह से प्रदत्त आंकड़े जांच के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।
 - iv. जिस अवधि के लिए ई यू से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, उस अवधि के लिए आंकड़ों को जांच से अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि शुल्क लगाए जाने से आयात में अचानक कमी आएगी जिससे घरेलू उद्योग का वास्तविक एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। यह एक अस्थायी स्थिति थी और शुल्क समाप्त किए जाने के बाद विभिन्न स्रोतों से भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धी आयात हुए। प्रदत्त सूचना से घरेलू उद्योग की बिक्री में स्वाभाविक या संभावित गिरावट का पता नहीं चलता है।
 - v. डी एस एम ने इस बात से इंकार किया है कि आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री और कीमत कटौती हुई है। पुनः विक्रेताओं के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत डी पी सी ओ कीमत से स्वाभाविक रूप से कम होगी ताकि पुनः विक्रेताओं को व्यय एवं उचित मार्जिन उपलब्ध कराया जा सके। घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत डी पी सी ओ कीमत से कम रही है। यदि बिक्री डी पी सी ओ कीमत पर की जाती तो कोई घाटा न हुआ होता। वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह जांच परिणाम न्यायोचित नहीं है कि डी एस एम से आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम था क्योंकि आयातों का पहुंच मूल्य डी पी सी ओ कीमत के आसपास है।
 - vi. घरेलू उद्योग की बनाने और बेचने की लागत में लगभग 50% की भारी कमी की गई है जबकि बिक्री कीमत में लगभग 15% की कमी की गई है। कीमत में मामूली गिरावट से भारी घाटा नहीं हो सकता।
 - vii. कम कीमत पर हुए निर्यातों के कारण घरेलू उद्योग को भारी घाटा हुआ है। इस बात को सोचा नहीं जा सकता कि घरेलू उद्योग निर्यात कीमत को किस प्रकार लाभकारी पाता है और निर्यात बढ़ाने का विकल्प चुनता है जबकि उसका तर्क यह है कि स्थानीय बाजार में अत्यधिक उच्च कीमत से क्षति हो रही है।
 - viii. वर्ष 2001-02 से घरेलू उद्योग की उत्पादकता दोगुनी हो गई है। तथापि, ये आंकड़े संबद्ध वस्तु के लिए नहीं हैं।

- ix. इस अभिमत का समर्थन आंकड़ों से नहीं किया गया है कि लगाई गई पूंजी पर आय में भारी कमी आई है ।
- x. मालसूची अनुचित रूप से अधिक नहीं है जिससे क्षति का संकेत नहीं मिलता है ।

विविध अनुरोध

- i. शुल्क आरोपित क्षति से अधिक है ।
- ख. मै. पिरामल हेल्थ केयर लि. (पूर्ववर्ती मै. निकोलस पिरामल इंडिया लि.) के अनुरोध

घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार से संबंधित अनुरोध

- i. मै. पिरामल हेल्थ केयर लि. ("मै. निकोलस पिरामल इंडिया लि." जैसा कि मूल जांच अवधि के दौरान जाना जाता था) । घरेलू उद्योग ने 30 सितंबर, 2010 से थाणे, महाराष्ट्र में स्थित प्रचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिए थे ताकि वह अपने प्रचालन डिगवाल, आंध्र प्रदेश में स्थापित अपने एक अन्य संयंत्र में दिसंबर, 2010 से शुरू कर सके तथा नए संयंत्र में विचाराधीन उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन पुनः शुरू हो गया है । मै पिरामल हेल्थ केयर लि., विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में स्पष्ट तौर पर पात्र है और वह भारत में संबद्ध वस्तु का संपूर्ण उत्पादन करता है । मै. पिरामल हेल्थ केयर लि. ("मै. निकोलस पिरामल इंडिया लि." जैसा कि मूल जांच अवधि के दौरान जाना जाता था) अभी भी भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक बना हुआ है ।
- ii. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सतत और अधिक पाटन के कारण घरेलू उद्योग मूल चरण से विनिर्माण बंद करने और विनिर्माण स्थल तथा प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हुआ ताकि वह संबद्ध देशों से हुए अनुचित आयातों के साथ कारगर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सके ।

गोपनीयता से संबंधित अनुरोध

- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी डी एस एम के दावे के अनुसार, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन आदि की संपूर्ण गणना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है । उसने स्वयं आंकड़े चुनिंदा ढंग से उपलब्ध कराए हैं ।
- ii. यद्यपि डी एन पी द्वारा गोपनीयता संबंधी आरोप लगाया गया है, तथापि उन्होंने प्राधिकारी के समक्ष स्विटजरलैंड के कुल बिक्री संबंधी आंकड़ों का प्रकटन भी नहीं किया है ।

विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के बारे में अनुरोध

- i. प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद को विटामिन ए पामीटेट के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सभी क्षमताओं और रूपों में विटामिन ए पामीटेट 1.7 एम आई यू/ग्राम तथा

विटामिन ए पामीटेट 1.0 एम आई यू/ग्राम शामिल है । अतः विचाराधीन उत्पाद तथा "समान वस्तु" के क्षेत्र के मुद्दे का प्राधिकारी ने समुचित निर्धारण किया है और इसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं है ।

- ii. इस बात से इंकार किया जाता है कि विटामिन ए एसीटेट क्रिस्टल्स तथा विटामिन ए पामीटेट 1.7 समान वस्तुएं हैं । ये क्रिस्टल एसीटेट रूप में हैं और घरेलू उद्योग प्रौद्योगिकी जानकारी तथा विटामिन ए क्रिस्टलों को विटामिन ए पामीटेट 1.7 में परिवर्तन करने की अवसंरचना के साथ एकमात्र घरेलू विनिर्माता है ।

निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन से संबंधित अनुरोध

- i. डी एस एम सहित स्विटजरलैंड के निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना अर्थात् तीसरे देश की सूचना (यूरोपीय संघ) अथवा पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत यथानिर्धारित विधिवत समायोजित भारत में संदत्त या संदेय कीमत के आधार पर परिकलित लागत पर आधारित होनी चाहिए था । प्राधिकारी ने डी एस एम के लिए सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का सही निर्धारण किया है । इस सीमा तक डी एस एम का आरोप झूठा है ।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डी पी सी ओ कीमतों के बेंचमार्क की सीमा तक शुल्क की सिफारिश नहीं की है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 14 सितंबर, 2007 के अंतिम जांच परिणाम में इस मुद्दे का समुचित निर्धारण किया है और इसलिए इस बारे में डी एस एम के आरोप को अस्वीकार किया जाता है ।
- iii. प्राधिकारी सहयोगी आयातकों द्वारा आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित व्यापक आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करने के लिए अधिदेशित हैं । तथापि, ऐसा कोई उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त पुनः विक्रेता द्वारा दायर किया गया प्रतीत नहीं होता है । अतः उक्त पुनः विक्रेता की सूचना स्वीकार किए जाने से स्थापित परंपरा का अनुचित उल्लंघन होगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी डी पी सी ओ कीमतों के संबंध में पुनः विक्रेता के लाभ मार्जिन हेतु कोई समायोजन करने के लिए न्यायोचित रूप से अनिच्छुक हैं ।
- iv. यह अनुरोध नितांत अप्रासंगिक है कि नेशनल फार्मास्युटीकल प्राइजिस अथॉरिटी (एन पी पी ए) की वैबसाइट पर भरोसा किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें उल्लिखित मार्जिन नुस्खों से संबंधित है न कि बल्क औषधि से ।
- v. आयात आंकड़ों से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई थी ।

- vi. डी एसएम द्वारा विटामिन ए क्रिस्टलों के संबंध में उल्लिखित क्षमता उपयोग में वृद्धि वाणिज्यिक पूर्व मिश्रणों की मांग में वृद्धि के कारण हुई है । विटामिन ए क्रिस्टलों का उपयोग खाद्य एवं आहार पूर्व मिश्रणों के निर्माण में आबद्ध खपत हेतु किया जाता है । जांच अवधि के दौरान विटामिन ए पामीटेट 1.7 के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है ।
- vii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु में लगातार वृद्धि हुई है परंतु उसमें जांच अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है ।
- viii. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और कुल बिक्री में एक समान प्रवृत्ति रही है और वर्ष 2003-04 तक भारी वृद्धि होने के बाद उसमें अत्यधिक गिरावट आई है ।
- ix. संबद्ध देशों से पाटित आयातों में समग्र रूप में तथा भारत में आयातों, भारत में उत्पादन और भारत में खपत की तुलना में भी वृद्धि हुई है ।
- x. आयात मात्रा में वृद्धि मांग में वृद्धि से काफी अधिक हुई है जिससे घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा प्रभावित हुआ है ।
- xi. संबद्ध देशों से पाटित कीमतें और आयातों की परिणामी पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति तथा क्षति रहित कीमत से कम रही है जिससे अत्यधिक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई है ।
- xii. लाभ में गिरावट से संबंधित डी एम एस के अनुरोध झूठे और मात्रा अनुमान पर आधारित हैं । वस्तुतः पिछले 5 वर्षों में घरेलू बाजार में बिक्री की तुलना में विचाराधीन का निर्यात नगण्य हुआ है । अतः यह पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर लगातार दबाव से स्पष्ट होता है कि घरेलू बिक्री में भारी घाटा हुआ है और वह लाभ की स्थिति से वित्तीय घाटे की हालत में पहुंच गया है ।
- xiii. कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है जबकि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की मजदूरी में भारी वृद्धि हुई है ।
- xiv. क्षति अवधि के दौरान वित्तीय घाटे के कारण नकद प्रवाह तथा लगाई गई पूंजी पर आय में भी भारी गिरावट आई है ।
- xv. डी एस एम द्वारा उसकी अपील में लगाए गए यह आरोप कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, गलत, गुमराह करने वाले और निराधार हैं ।

विविध अनुरोध

- i. पुनः न्याय निर्णयन प्राधिकारी वापसी आदेश एवं शक्तियों से आगे नहीं जा सकते और निम्न स्तर के प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र वापस किए गए मामले तक ही सीमित होता है। वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी नए मुद्दे पर न्याय निर्णयन देने से प्रतिबंधित है जो सेस्टेट के आदेश के दायरे के बाहर है।
- ii. याचिकाकर्ताओं में सेस्टेट के समक्ष इस आधार पर अपनी अपील में तर्क नहीं दिया कि जिस निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मामले की सुनवाई की, उसने अंतिम जांच परिणाम पारित नहीं किए। मै. डी एस एम न्यूट्रीशनल द्वारा किए गए सभी दावे और उठाए गए मुद्दे घरेलू उद्योग के रूप में मै. मिरामल हेल्थ केयर के दर्जे से संबंधित है।
- iii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उस स्थिति में भी बी एस एम के आंकड़ों को स्वीकार किया है जब वे समूची जांच के दौरान असहयोगी रहे हैं।
- iv. नए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष किसी दूसरी सुनवाई की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी पक्षकार ने नए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष किसी नई सुनवाई की मांग नहीं की है। अतः माननीय सेस्टेट का आक्षेपित आदेश वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।
- v. डी एस एम वर्ष 2006 में मध्यावधि समीक्षा उस समय दायर कर सकता था जब यह आरोप लगाया गया था कि घरेलू उद्योग विटामिन ए एसीटेट क्रिस्टलों का आयात कर रहा है। डी एस एम ने ऐसी किसी "परिस्थितियों में परिवर्तन" को सिद्ध करते हुए नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत ऐसी कोई समीक्षा दायर नहीं की और न ही डी एस एम ने इस संबंध में अपनी अपील में संशोधन किया।
- vi. प्राधिकारी को डी एस एम को "असहयोगी" मानना चाहिए और उसने डी एस एम को अनुचित रूप से प्रदत्त अलग मार्जिन के स्थान पर डी एस एम हेतु अवशिष्ट शुल्क की सही सिफारिश की है।

प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां

(16) प्राधिकारी को घरेलू उद्योग और मै. डी एस एम दोनों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। प्रकटन विवरण में दिए गए ब्यौरे के तथ्यों से मौटे तौर पर सहमत हैं तथापि, मै. डी एस एम ने जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रूप में निकाले पिरामिल की स्थिति को स्वीकार करते हुए पाटन मार्जिन के निर्धारण, क्षति मार्जिन के निर्धारण और पाटन मार्जिन गणनाओं संबंधी कुछ मापदंडों को प्रकटन नहीं किए जाने के संबंध में अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी मापदंडों के

संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर संगत समझी गई सीमा तक इन जांच परिणामों के उचित स्थानों पर पहले ही विचार किया गया है। तदनुसार इन जांच परिणामों में 13 दिसंबर, 2011 को प्राधिकारी द्वारा निर्णयोपरांत सुनवाई सहित जांच की प्रक्रिया में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी टिप्पणियों को शामिल किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

(16) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी ने उस सीमा तक निम्नानुसार विचार किया है जिस सीमा तक वे संगत पाए गए हैं :

घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

- i. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के आधार के बारे में किए गए अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने 14 सितंबर, 2007 के अपने अंतिम जांच परिणाम में भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र ज्ञात उत्पादक होने के कारण मै. निकोलस पिरामल इंडिया लि. एन पी आई एल को घरेलू उद्योग माना था जिसने नियमों में निर्धारित उपबंधों की पूर्ति की थी। समूची जांच के दौरान किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने मै. एन पी आई एल के बारे में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया कि वह याचिका दायर करने की पात्र नहीं है।
- ii. मै. डी एन पी का यह तर्क वर्तमान जांच के लिए अप्रासंगिक है कि मै. एन पी आई एल ने दिसंबर, 2010 से मूल चरण से विटामिन ए पामीटेट का उत्पादन बंद कर दिया है। क्योंकि यह जांचोत्तर घटनाक्रम है। इसके अलावा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन होने से घरेलू उत्पादक "घरेलू उद्योग" के दर्जे का अपात्र नहीं बन जाता है बशर्ते उसने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन जारी रखा हो। यदि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग के सतत दर्जे को चुनौती देनी थी तो वे पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ परिवर्तित परिस्थितियों की पुष्टि करते हुए मध्यावधि समीक्षा हेतु आवेदन कर सकते थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध जांच में जांच अवधि 1 अप्रैल, 2004 से 30 सितंबर, 2005 (18 माह की अवधि) की थी। अतः घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु की विनिर्माण प्रक्रिया में परिवर्तनों और/अथवा उसे जारी रखने या बंद करने के बारे में कोई परिवर्ती घटनाक्रम वर्तमान वापसी प्रक्रिया के क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। यदि घरेलू उद्योग की संरचना में जांचोत्तर अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी नियमों के संगत उपबंधों के अनुसार परिवर्तित परिस्थितियों, यदि कोई हो, के लिए समीक्षा की ही मांग कर सकते हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग के रूप में मै. पिरामल हेल्थ केयल लि. ("मै. निकोलस पिरामल इंडिया लि." जैसा कि मूल जांच अवधि के दौरान जाना जाता था) के आधार की पुनः पुष्टि करते हैं।

- iii. एक ओर विपक्षी हितबद्ध पक्षकार यह तर्क देते हैं कि विटामिन ए पामीटेट और विटामिन ए ऐसीटेट समान वस्तुएं हैं और इसी के साथ यह आरोप लगाते हैं कि निकोलस पिरामल घरेलू उद्योग नहीं है क्योंकि वह इस समय विटामिन ए ऐसीटेट को विटामिन ए पामीटेट में परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब किसी मध्यवर्ती निविष्टि को रासायनिक प्रक्रिया के जरिए अंतिम उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, तो परिवर्तन की प्रक्रिया को विनिर्माण नहीं माना जाता है और ये दोनों समान वस्तुएं नहीं हो सकती हैं । इसके अलावा, उत्पाद पद्धति, प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया में परिवर्तन से घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग के दर्जे का अपात्र नहीं बन जाता है जब तक कि वह संबद्ध वस्तु के उत्पादन और आपूर्ति का कार्य कर रहा हो ।

निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन

- iv. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता मै. डी एन पी ने माननीय सेस्टेट के समक्ष प्राथमिक रूप से स्विटजरलैंड में घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का तर्क दिया है जिसे संबद्ध वस्तु की कुल बिक्री के 2% से कम बताया गया है और इस प्रकार वह सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्रतिनिधिक नहीं है । मै. डी एन पी ने यह भी तर्क दिया है कि व्यापार के स्तर, आदेश की मात्रा के अलग-अलग स्तरों पर आधारित बिक्री आदि से संबंधित उसके कुछेक दावों पर प्राधिकारी ने 14 सितंबर, 2007 के अपने जांच परिणाम में विचार नहीं किया था । तथापि, मै. डी एन पी ने इस संबंध में अपने दावे की पुष्टि करने के लिए किसी दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित कोई अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की है ।
- v. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच करते समय प्राधिकारी ने 14 सितंबर, 2007 के अंतिम जांच परिणाम में निम्नानुसार मत व्यक्त किया था :-

"59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** किग्रा. 17 एम आई यू/जी एम के निर्यात की तुलना में उसी अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** किग्रा. विटामिन ए पामीटेट 1.7 एम आई यू /जी एम और *** कि.ग्रा. *** एम आई यू /जी एम की बिक्री की थी । अतः करार के अनुसार ऐसा घरेलू बाजार की बिक्रियों की पर्याप्त मात्रा होने के कारण सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उन पर विचार किया जाना अपेक्षित है और तदनुसार, प्राधिकारी ने निर्यातक देश के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इन बिक्रियों पर विचार किया है ।

60. तथापि, निर्यातक ने यह दलील दी है कि यदि सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ घरेलू बाजार में उनकी बिक्रियों पर विचार किया जाना अपेक्षित है तो बिक्री मात्राओं और व्यापार के स्तर में अंतर पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू बिक्रियां सीधे खुदरा ग्राहकों को कम मात्राओं में की जाती हैं और इसलिए वे निर्यात बिक्री सौदों के साथ तुलनीय नहीं हैं । दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के पत्र के माध्यम से निर्यातक से व्यापार समायोजनों के स्तरों तथा उचित तुलना हेतु उनके द्वारा किए गए दावों के अनुसार कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों को

निर्धारित करने एवं उन्हें दर्शाने को कहा गया था । अपने दिनांक 24 अप्रैल और 16 मई, 2007 के पत्र के माध्यम से निर्यातक ने स्विट्जरलैंड में सीधे ग्राहकों को कम मात्राओं में बिक्रियों के कारण घरेलू बिक्रियों के संबंध में कीमत तुलनीयता और प्रत्यक्ष बिक्री व्ययों को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए समायोजनों को निर्धारित करने के लिए कुछेक सूचना एवं तर्क प्रस्तुत किए थे ।

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध 1 के नियम 6 (i) तथा करार के अनुच्छेद 2.4 में यह प्रावधान है कि "प्रत्येक मामले में अर्हता के आधार पर व्यापार की स्थितियों एवं निबंधनों के अंतर, कराधान, व्यापार का सतर, मात्रा, भौतिक विशेषताएं तथा अन्य अंतर जिनसे कीमत तुलनीयता का प्रभावित होना प्रदर्शित होता है, सहित कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले अंतरों के लिए उचित छूट दी जाएगी । "उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्यातक के दावों की निम्नानुसार जांच की गई है :-

(क) घरेलू बाजार में सौदे की कम मात्रा के लिए समायोजन के निर्यातक के दावे की जांच की गई है । यह दावा किया गया है कि घरेलू बिक्रियां कम मात्राओं में हैं और घरेलू बाजार में प्रति सौदा बेची गई औसत मात्रा 41 कि.ग्रा. है जबकि भारतीय बाजार में प्रति बिक्री औसत मात्रा 416 कि.ग्रा. है । यह तर्क दिया गया है कि ऑर्डर की मात्रा में अंतर से संबंधित कीमतों पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे कम ऑर्डर मात्राओं पर एक न्यूनतम मात्रा सरचार्ज लेते हैं । इसके समर्थन में कम मात्रा वाले कुछ निर्यात बीजक प्रस्तुत किए गए हैं । तथापि, घरेलू बाजार में कम ऑर्डर सरचार्ज का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि मात्राओं का कीमत पर सीधा प्रभाव पड़ता है और तुलना के प्रयोजनार्थ समायोजन किया जाना अपेक्षित है । तदनुसार निर्यातक ने भारत में बिक्री सौदों हेतु 300 कि.ग्रा. से कम और 300 कि.ग्रा. से अधिक मात्रा की प्रति इकाई कीमत में अंतर के आधार पर समायोजन का निर्धारण किया है । तथापि, ये मात्रा और कम मात्रा सरचार्ज निर्यात बिक्री के संदर्भ में हैं और गृह बाजार में मात्राओं के कारण कीमतों में ऐसे किसी अंतर का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः प्राधिकारी का यह मत है कि ऐसे समायोजन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

(ख) मात्राओं के संबंध में समायोजनों के अलावा निर्यातक ने इन आधारों पर व्यापार समायोजन के स्तर का दावा किया है कि घरेलू बिक्रियां अधिकांशतः प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं को की गई हैं जबकि भारत को निर्यात बिक्रियां अधिकांशतः पुनः बिक्रीकर्ताओं को की गई हैं, इससे भी कीमत तुलनीयता पर प्रभाव पड़ता है । यह तर्क भी दिया गया है कि स्विट्जरलैंड या यूरोपीय बाजारों में प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं की कीमतें पुनः बिक्रीकर्ताओं के कीमतों की तुलना में आमतौर पर 5 से 7% अधिक होती है । इस दावे के समर्थन में उन्होंने प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं और स्विस बाजार में पुनर्बिक्रीकर्ताओं को उसी उत्पाद के समकालीन बीजकों के साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है जिनसे यह संकेत मिलता है कि इन कीमतों में पिच लगभग 5% का अंतर है । यह तर्क दिया गया है कि पुनः बिक्रीकर्ताओं को इस इस चिन्हांकन की अनुमति दी गई है ताकि वह अपने खर्चों और लाभ पर ध्यान रख सकें । आमतौर पर पुनः बिक्रीकर्ता या एजेंट को एक कमीशन, या अपनी कीमतों में एक चिन्हांकन प्राप्त होता है जो व्यापार में सामान्यतः उसके खर्चों और मार्जिनों तथा 3 से 5% तक कमीशन/मार्जिन की पूर्ति हेतु होता है । अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि इसके लिए 3% का समायोजन न्यायोचित है ।

(ग) निर्यातक ने घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष बिक्री खर्चों अर्थात् संयंत्र से भाण्डागारों तक अंतर्देशीय भाड़ा और संबंधित बीमा, भण्डारण एवं प्रहस्तन व्यय, भांडागार से उपभोक्ता तक ले जाने का भाड़ा और संबंधित बीमा खर्च के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। जहां तक भाण्डागारों से घरेलू उपभोक्ताओं तक के घरेलू मालभाड़े का संबंध है, निर्यातक ने डी एच एल कुरियर के जरिए की गई सुपुर्दगी में आई वास्तविक लागत के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और तदनुसार संशोधित मालभाड़ा लागत की गणना *** अम.डालर प्रति कि.ग्रा. के रूप में की गई है।

62. तदनुसार, स्विटजरलैंड में विचाराधीन उत्पाद के लिए कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निम्नानुसार ज्ञात किया गया है :

घरेलू बाजार में प्रतिनिधि कीमत	मात्रा कि.ग्रा. में	यूरो में कीमत	अम.डॉ. में कीमत	विनिमय दर	समायोजन अम.डा./ कि.ग्रा.	सामान्य मूल्य अम.डा./ कि.ग्रा.
विटा. ए पाम 1.7 बी एच ए/बीएचटी	***	***	***	***	***	***
विटा. ए पाम 1.7 टी ओ सी ओ	***	***	***	***	***	***

(ख) निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन

(i) डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स

63. डी एन पी जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु के *** कि.ग्रा. की निर्यात बिक्रियों की जानकारी दी है जिसमें विटामिन ए पाल्मिटेट 1.7 बी एच ए/बी एच टी और 1.7 टी ओ सी ओ शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को बिक्री हेतु डी एन पी के उत्पाद सामान्यतः भारत को भेजे जाने से पहले नीदरलैंड से सिंगापुर को भेजे (जलपोत द्वारा) जाते हैं। निर्यातक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि इन संबंधित उत्पादों का प्रहस्तन डी एस एम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के सिंगापुर में एशिया पैसिफिक हेतु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। यह एक भाण्डागार के साथ एक व्यापारिक संगठन है और उत्पादों का भारत को और अन्य एशिया पैसिफिक देशों को पुनः निर्यात करता है। निर्यातक ने अनुरोध किया है कि प्रश्नावली के उत्तर में बताई गई कीमतें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अंतिम निर्यात कीमत है और संबंधित कंपनियों अर्थात् डी एन पी स्विटजरलैंड और डी एन पी सिंगापुर के बीच कीमत तंत्र इस जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है।

64. निर्यातक ने सिस्सेन स्थल से वेनलो, नीदरलैंड (भाण्डागार) तक के अंतर्देशीय मालभाड़े और संबंधित बीमा खर्चों; और पोत परिह्वहन प्रभारों पर हुए प्रत्यक्ष बिक्री के संबंध में सूचना प्रदान की है। पैकिंग खर्चों के संबंध में किसी समायोजन का दावा नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें लागत में शामिल

किया गया है और निर्यात पैकिंग के बीच कोई अंतर नहीं है । तदनुसार, कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निम्नानुसार बनती है :

भारत को निर्यात कीमत	मात्रा कि.ग्रा. में	कीमत यूरो	दर यूरो/कि.ग्रा.	मूल्य अम.डॉ./ कि.ग्रा.	दर अम.डॉ./कि.ग्रा.	समायोजन अम.डॉ./ कि.ग्रा.	निवल कीमत अम.डॉ./ कि.ग्रा.
विटा.ए पाम 1.7 बीएचए/बीएचटी	***	***	***	***	***	***	***
विटा.ए पाम 1.7 टी ओ सी ओ	***	***	***	***	***	***	***

65. स्विट्जरलैंड के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य और डी एन पी के लिए निर्धारित निवल निर्यात कीमत के आधार पर इस सहयोगी निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन का आकलन निम्नानुसार किया गया है :

	सामान्य मूल्य अम.डा./कि.ग्रा.	मात्रा कि.ग्रा.	निर्यात कीमत अम.डा./कि.ग्रा.	मात्रा कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन अम.डा./कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन मूल्य
विटा.ए पाम 1.7 बीएचए/बीएचटी	***	***	***	***	***	***
विटा.ए पाम 1.7 टी ओ सी ओ	***	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***	***

66. डी एस एम ने अपने प्रकटन के बाद अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि चूंकि भारतीय कानून में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्त मात्राओं में माने जाने के लिए घरेलू बिक्रियों हेतु निर्धारित सीमा की व्यवस्था नहीं है इसलिए प्राधिकारी को इस संबंध में केवल डब्ल्यूटीओ करार पर विश्वास नहीं करना चाहिए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्विट्जरलैंड में की गई घरेलू बिक्रियां उसके कुल बिक्रियों की तुलना में काफी कम (2%) से कम थीं, अपनी खुद की बुद्धिमता के आधार पर इसका मूल्यांकन करना चाहिए । यह भी तर्क दिया गया है कि किसी बाजार विशेष की स्थिति अर्थात् स्विट्जरलैंड में बिक्रियां काफी कम मात्राओं में की गई हैं जबकि भारत को निर्यात के लिए की गई बिक्रियां स्विट्जरलैंड में बिक्रियां काफी अधिक मात्राओं में की गई हैं जिस पर स्विट्जरलैंड में सामान्य मूल्य के निर्धारण में विचार किया जाना चाहिए । उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए यूरोपीय संघ उपयुक्त बाजार है और न कि स्विट्जरलैंड । निर्यातक ने यह भी टिप्पणी की है कि भारित औसत पाटन मार्जिन की गणना भारित औसत सामान्य मूल्य और भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर की जानी चाहिए ।

67. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन के बाद अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि मौके पर सत्यापन किए बिना डी सी एम द्वारा दिए गए आंकड़ों और अन्य दावों को स्वीकार करना अनावश्यक है और तथ्यरहित नहीं है। घरेलू उद्योग ने आगे यह भी तर्क दिया है कि उपर्युक्त परिसिथितियों में डी एस एम समेत स्विटजरलैंड के निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना अर्थात् तीसरे देश (यूरोपीय संघ) की सूचना या भारत में दी गई या देय कीमत जो नियमों के अंतर्गत यथानिर्धारित ढंग से विधिवत रूप से समायोजित हो, पर आधारित होना चाहिए।

68. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्विस् बाजार में की गई बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्राओं में की गई पाई गई हैं (जो भारत को बिक्रियों का 20% से अधिक हिस्सा है) और इसलिए इनमें भारत को निर्यातों के साथ तुलना के लिए उपयुक्त समझा गया है तथापि, निर्यातक ने कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले कतिपय कारकों के संबंध में अपने घरेलू बाजार की कीमतों में कुछेक समायोजनों का दावा किया है और ऐसे समायोजन जो निर्यातक द्वारा प्रदर्शित एवं साक्ष्यों के साथ उचित ठहराए जा सकते हैं, को प्राधिकारी ने स्वीकार किया है। न्यूनतम मात्रा संबंधी के लिए किए गए समायोजनों का दावा घरेलू बिक्रियों के संदर्भ के निर्यातक द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सका है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में निर्यातक के तर्क व्यवहार्य नहीं हैं। जहां तक गणना किए गए पाटन मार्जिन में हुई गलती का संबंध है, पाटन मार्जिन का निर्धारण मध्यवर्ती पाटन मार्जिनों के भारित औसत, सबटाइप स्तरों (उत्पाद सबटाइप्स की निर्यात मात्राओं पर भारित) पर निर्धारित के रूप में किया जाता है। उपर्युक्त निर्यातक के लिए उक्त आधार पर पाटन मार्जिन की गणना उचित है अतः पाटन मार्जिन में किसी परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है।

(17) प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के बारे में मै. डी एन पी के सभी अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा 14 सितंबर, 2007 के अंतिम जांच परिणामों में जांच की गई थी और विचार किया गया था। जहां तक उन्हें प्राधिकारी ने संगत पाया था और हितबद्ध पक्षकारों ने विधिवत पुष्टि की थी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी मै. डी एन पी, स्विटजरलैंड के बारे में प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की पुनः पुष्टि करते हैं।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

(18) मै. डी एन पी ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति औषध कीमत नियंत्रण आदेश (डी पी सी ओ) के अंतर्गत सरकार द्वारा नियंत्रित की जा रही संबद्ध वस्तु के कारण हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों से इतर कारणों की वजह से घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति का निर्धारण और उसे पृथक किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में प्राधिकारी ने 14 सितंबर, 2007 के अपने जांच परिणाम में निम्नानुसार नोट किया

"131. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में एन आई पी का निर्धारण प्राधिकारी की सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार जांच अवधि के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। विटामिन ए पामिटेड 1.7 एम आई यू/ग्राम के लिए एन आई पी का निर्धारण *** रु./प्रति किग्रा. किया गया है। 27.3.2007 से एन पी ए द्वारा निर्धारण मौजूदा डी पी सी ओ कीमत 4564.50 रु./कि.ग्रा. है जिसे 2005-06 की अवधि के लिए लागत के आंकड़ों के आधार पर तय किया माना जाता है। प्राधिकारी द्वारा जिस अवधि के लिए आंकड़ों की जांच की गई है उस अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2004 से 30 सितंबर, 2005 तक के 18 माहों में अप्रैल, 2005-मार्च, 2006 के लिए एन पी ए द्वारा जांच किए गए 12 माह के आंकड़ों की तुलना में पर्याप्त अंतर है। इसके अलावा एन पी ए तथा प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्राप्ति की दर स्पष्टतः अलग-अलग है। अतः क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु डी पी सी ओ के तहत एन पी पी ए की वर्तमान कीमत को अपनाना उचित नहीं होगा। इसी तर्क के आधार पर इस मामले में क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु पूर्ववर्ती अवधि की एन पी पी ए कीमत भी उचित नहीं होगी। अतः क्षति मार्जिन निकालने के लिए प्राधिकारी ने उपर्युक्तानुसार निर्धारित एन आई पी की तुलना उचित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की है।

132. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान डी पी सी ओ अधिकतम कीमत से वह अधिकतम कीमत तय हुई थी जिस पर घरेलू उद्योग, घरेलू बाजार में वस्तु की बिक्री कर सकता था। अतः अहेतुक मानकों के अनुसार इस अधिकतम कीमत के कारण घरेलू उद्योग को हो सकने वाली क्षति, यदि कोई हो, का कारण पाटित आयातों को नहीं माना जा सकता और पाटित आयातों के क्षति मार्जिन को जांच अवधि के दौरान प्रचलित डी पी सी ओ कीमत से कम पर हुए पाटित आयातों की मात्रा तक सीमित किया जा सकता है। तदनुसार पाटित आयातों के लिए जिस क्षति मार्जिन को आधार माना जा सकता है वह निम्नानुसार बनता है:-

देश	निर्यातक	एनआईपी	एलवी	जांच अवधि के दौरान डी पी सी ओ कीमत	क्षति मार्जिन	पाटित आयातों के कारण हुई क्षति	पाटित आयातों के कारण हुई क्षति
		रु./कि. ग्रा.	रु./कि. ग्रा.	रु./कि. ग्रा.	रु./कि. ग्रा.	रु./कि. ग्रा.	%
स्विट्जरलैंड	डी एस एम न्यूट्रिशनल उत्पाद	***	***	4125.9	***	***	5-15%
स्विट्जरलैंड	अन्य सभी	***	***	4125.9	***	***	15-25%
चीन.जन. गण.	सिनकेम के साथ एन एच क्यू	***	***	4125.9	***	***	10-20%
चीन.जन. गण.	अन्य सभी	***	***	4125.9	***	***	25-35%

(19) उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि मै. डी एन पी द्वारा डी पी सी ओ नियंत्रित कीमतों के कारण हुई क्षति के बारे में किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी ने 14 सितंबर, 2007 को जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम में विधिवत विचार और समाधान किया था ।

(20) प्राधिकारी ने 14 सितंबर, 2007 के अपने अंतिम जांच परिणाम में आगे निम्नानुसार मत व्यक्त किया :

"120. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों की इन दलीलों का संबंध है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति सरकारी कीमत और कम संबंधी नीतियों के कारण हुई है और इसका पाटित आयातों से कोई लेना-देना नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात का पहुंच मूल्य डी पी सी ओ कीमत से काफी कम है भले ही पुनर्विक्रेता के लिए तर्कसंगत मार्जिन पर विचार किया जाए जिससे ये संकेत मिलता है कि चाहे डी पी सी ओ कीमत को बेंचमार्क के रूप में लिया जाए, पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर उल्लेखनीय क्षतिकारी प्रभाव है । अतः निर्यातकों की दलील कि सरकारी नीतियां और डीपीसीओ कीमतें क्षति का एकमात्र कारण हैं, प्रमाणिक नहीं है ।

(21) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि डी एन पी के अनुरोध काल्पनिक और निराधार हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति औषध कीमत नियंत्रण आदेश (डी पी सी ओ) के अंतर्गत सरकार द्वारा नियंत्रित की जा रही संबद्ध वस्तु के कारण हुई है न कि पाटित आयातों के कारण ।

(22) जहां तक मै. डी एन पी द्वारा लाभ मार्जिन और विक्रेताओं के व्यय का प्रावधान करने के लिए पुनः विक्रेताओं हेतु बिक्री कीमत डी पी सी यू कीमत से कम होने के बारे में किए गए अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी ने 14 सितंबर, 2007 के अपने अंतिम जांच परिणाम में निम्नानुसार नोट किया था :

"हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि चूंकि डी पी सी ओ कीमत भारत में बिक्री की अधिकतम कीमत है इसलिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, के निर्धारण हेतु इस कीमत को ध्यान में रखना चाहिए और क्षति जांच अवधि के दौरान डी पी सी ओ कीमत के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण पाटित आयातों को नहीं माना जाना चाहिए । आगे यह तर्क दिया गया है कि डी पी सी ओ कीमत भारत में बिक्री की अधिकतम कीमत होने के कारण पुनर्विक्रेता के लाभ हेतु तुलना पर विचार किया जाना चाहिए । इसके समर्थन में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के बाद पुनर्विक्रेता की कुछ अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत की गई है जिसे पूर्व में उल्लिखित कारणों से रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सका । "

(23) यद्यपि, मै. डी एन पी द्वारा पुनः विक्रेताओं के मार्जिन के समायोजन के बारे में अनुरोध प्रकटन पश्चात किए थे तथापि, उन पर प्राधिकारी ने 14 सितंबर, 2007 के अंतिम जांच परिणाम में निम्नानुसार विचार किया जा चुका था :

"130. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन निर्यातकों के निर्यात सौदे सीधे ग्राहकों और पुनर्विक्रेताओं को होते हैं । आयातकों ने पुनर्विक्री कीमत तथा ऐसे आयातों पर उनके द्वारा किए गए एस जी ए व्यय अथवा अर्जित लाभ के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है । अतः प्राधिकारी क्षति मार्जिन की तुलना और निर्धारण के प्रयोजनार्थ डी पी सी ओ कीमत पर पुनर्विक्रेता के लाभ मार्जिन हेतु ऐसी छूट देने में कोई औचित्य नहीं पाते हैं ।"

(24) मै. डी एन पी, स्विटजरलैंड ने क्षति विश्लेषण के अन्य पहलुओं पर भी अपने अनुरोध दोहराए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षमता उपयोग, सीमाशुल्क में कमी, निर्यात कीमत, घरेलू बिक्री कीमत से कम होना, घरेलू उद्योग की उत्पादकता, लगाई गई पूंजी पर आय आदि शामिल हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक 14 सितंबर, 2007 के अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा चुका है । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित निष्कर्ष में 14 सितंबर, 2007 के अंतिम जांच परिणाम में निम्नानुसार नोट किया था ।

"छ.3.4 समग्र मूल्यांकन

115. कारकों का उपर्युक्त विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू बाजार में अच्छी मांग, उत्पादकता में सुधार और पिछले वर्षों की तुलना में इसकी उत्पादन लागत में कमी के बावजूद, उद्योग उत्पादन में गिरावट, और बिक्री; कम निवल बिक्री वसूली; उच्चतर भंडारण सूची; निवेश और लाभ पर नकारात्मक या कम आय के कारण क्षति का सामना कर रहा है । क्षति जिसको वहन किया जा रहा है वास्तविक और काफी है । अतः हितबद्ध पक्षकारों की दलीलें कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को किसी वास्तविक क्षति का सामना नहीं करना पड़ रहा है, प्रमाणिक नहीं है ।"

गोपनीयता

(25) जहां तक मै. डी एन पी के इस अनुरोध का संबंध है कि प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के कार्यप्रणाली का उसे प्रकटन नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति मार्जिन की गणना घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत पर आधारित है और यह गोपनीय होने के कारण इसका प्रकटन नहीं किया जा सकता । जहां तक पाटन मार्जिन की कार्यप्रणाली से संबंधित सूचना का प्रश्न है, मै. डी एन पी ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण पर 31 अगस्त, 2007 की अपनी टिप्पणियों में निम्नानुसार उल्लेख किया था :

"हम आगे यह अनुरोध करते हैं कि पाटन मार्जिन की गणना में त्रुटि प्रतीत होती है । प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार औसत भारत सामान्य मूल्य *** होना चाहिए और भारत निर्यात कीमत *** होनी चाहिए । इससे *** का पाटन मार्जिन उपलब्ध होगा ।"

मै. डी एन पी की उपर्युक्त टिप्पणियों का तात्पर्य यह है कि उसे अपेक्षित सूचना की पर्याप्त जानकारी थी ।

विविध अनुरोध

(26) जहां तक मै. डी एन पी के इस अनुरोध का संबंध है कि लगाया गया शुल्क आरोपित क्षति से अधिक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा 14 सितंबर, 2007 के अपने अंतिम जांच परिणाम में संस्तुत शुल्क पाटन एवं क्षति मार्जिन से कमतर है और इसलिए यह नियमानुसार तर्कसंगत है ।

निष्कर्ष एवं सिफारिश

(27) माननीय सेस्टेट के दिनांक 11 अगस्त, 2011 के आदेशों के अनुपालन में प्राधिकारी द्वारा आयोजित निर्णयोपरांत सुनवाई के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच करने और उन पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा 14 सितंबर, 2007 की अधिसूचना सं. 14/11/2005-डी जी ए डी के तहत जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है । अतः प्राधिकारी एतद्वारा 14 सितंबर, 2007 की अधिसूचना सं. 14/11/2005-डी जी ए डी के तहत निकाले गए अपने अंतिम जांच परिणाम और उसमें की गई सिफारिशों की पुनः पुष्टि करते हैं ।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th February, 2012

CESTAT Remanded Post Decisional Hearing Findings

Subject : Anti-Dumping Investigation concerning imports of Vitamin-A Palmitate originating in or exported from Switzerland and China PR.

No. 14/11/2005-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules) thereof:

Background of the case:

- 1) M/s Nicholas Piramal India Limited (NPIL) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) under the above referred Act and the Rules, alleging dumping of Vitamin-A Palmitate (hereinafter referred to as the subject goods) and consequent injury, originating in or exported from Switzerland and China PR (hereinafter referred to as the subject countries), and requested for levy of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries.
- 2) The product involved in the subject investigation is Vitamin A Palmitate. Vitamin Palmitate is manufactured in various strengths and forms and due to technical and commercial substitutability of these grades Vitamin-A Palmitate of all concentrations and forms were included within the product under consideration.

- 3) The Authority initiated an anti-dumping investigation in respect of the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; vide Notification No. 14/11/2005-DGAD dated 23rd March 2006. The period of the said investigation (POI) was from 1st April 2004 to 30th September 2005 and the injury period covered 2000-01 to 2003-04.
- 4) In response to the notice of initiation, the interested parties including the appellant before the CESTAT filed response in the prescribed proforma and also made written submissions.
- 5) The Authority issued the preliminary findings vide Notification No. 14/11/2005-DGAD dated 20th February 2007 recommending provisional duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and the Department of Revenue imposed the provisional duty vide Notification No. 47/2007-Customs dated 28th March, 2007.
- 6) M/s DSM Nutritionals Product Ltd (DNP) filed detailed comments on the preliminary findings, wherein they pointed out, that the examination of the injury parameters on the basis of the information submitted by domestic industry, clearly shows a total absence of injury. The determination of the Non Injurious Price (NIP) was also challenged on the ground that under the Drugs Price Control Order (DPCO) a maximum price had been fixed under law and therefore, the NIP could not be fixed without regard to such price, as the domestic industry could not have sold its products at a price above that fixed under the DPCO.
- 7) The Authority issued the final findings on 14th September 2007 recommending definitive duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and the Department of Revenue imposed the definitive duties vide Notification No. 112/2007-Customs dated 30th October, 2007. This definitive duty was made effective from 28.3.2007 i.e., the date of the imposition of the provisional duty.

- 8) Aggrieved by the final findings issued by the Authority on 14th September 2007 and the Custom notification issued by the Department of Revenues vide Notification No. 112/2007-Customs dated 30th October, 2007, M/s DSM Nutritional Product Ltd, having its registered office in Switzerland, filed an appeal before the Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) New Delhi, under Section 9(C) of the Custom Tariff Act 1995.
- 9) The Hon'ble CESTAT, New Delhi, vide its order dated 11.08.2011, disposed the petition. The operative part of the said order, inter alia, is as follows:

"15. Accordingly we allow these appeals by remand to the DA for affording post-decisional hearing to the appellants and for making such modifications to the final findings as may be necessary as a result of such post-decisional hearing. The respondent-domestic industry and other interested parties, if any, shall also be allowed to participate in such post-decisional hearing. Any modifications made in the final findings would be considered by giving effect to the same by the Government by carrying out the necessary amendments to the impugned notifications imposing anti-dumping duty. This process shall be completed within 6 months from the date of this order and status quo-shall be maintained-meanwhile. Since we are allowing these appeals by remand, the related stay petitions, MAs and COs stand disposed off."

- 10) In compliance with the said orders of the CESTAT and without prejudice to the rights of the Designated Authority to challenge the said orders dated 11th August, 2011 of Hon'ble CESTAT on the matters of law and principle, the Authority held a post decisional oral hearing for the known interested parties on 13th December 2011.
- 11) The essential facts of the action of the Authority pursuant to the post decisional hearing held by the Authority in compliance with the orders dated 11th August 2011 of Hon'ble CESTAT were disclosed to the interested parties by the Authority and comments received thereon have been examined and addressed by the Authority at respective areas of this finding.

- 12) *** in this finding statement represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- 13) The submissions made by the interested parties in the written form, who attended the post decisional oral hearing are as follows:
- 14) The representatives of the following interested parties attended the post decisional oral hearing held by the Authority on 13th December, 2011 and made oral submissions:
 - a) M/s Nicolas Piramal India Ltd. (NPIL)
 - b) M/s DSM Nutritionals Product Ltd. (DNP)
- 15) The submissions made by the interested parties in writing, pursuant to the post decisional oral hearing, are as follows:

SUBMISSIONS MADE BY M/s DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD

Submissions concerning scope of Domestic Industry and Standing

- i. Nicholas Piramal is not a Domestic Industry as they have progressively moved away from manufacturing from Citral route to simply buying Vitamin A Acetate 2.8 miu/gm for single step conversion into Palmitate 1.7 miu/gm. During the hearing, it was admitted by the Counsel for Nicholas Piramal that at least from December 2010, the company has stopped production of Vitamin-A Palmitate from the basic stage and that they are presently only undertaking activities for conversion of Vitamin A Acetate to Vitamin A Palmitate.
- ii. The two forms of Vitamin A are like articles. Vitamin A Palmitate and Vitamin A acetate, can be used interchangeably, and are merely sub types of Vitamin A. The activity of conversion from one form of Vitamin A to another would not make Nicholas Piramal a domestic industry.

- iii. As Piramal is no longer a domestic industry, its right of participation, in the proceedings is also defeated. Piramal's factual submissions as to the nature of their manufacturing activities are misleading. The so called '*different production process*' is one of conversion from Vitamin A acetate to Vitamin A Palmitate. The conversion is not a process amounting to manufacture or production.
- iv. Mere fact that excise duty may have been paid on such activity, would not make it manufacture or production. Excise duty is paid by virtue of Note 10 to Chapter 32 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act covering vitamins, which provides that packing, repacking, relabeling or carrying out any process to make the product marketable, would amount to manufacture.

Submissions relating to confidentiality

- i. Neither the dumping margin, nor the injury margin calculation has been disclosed to DSM.
- ii. The Authority has failed to disclose the confidential calculations for the dumping and injury margins. The dumping margin is based exclusively on the information provided by the exporter, and therefore, the same ought to have been provided. Similarly, the final injury calculation is based on the DPCO prices, which are in the public domain.

Submissions relating to Export Price, Normal Value, Dumping Margin and Injury Margin

- i. Authority has determined normal value and dumping margin erroneously. In a situation where there are no sales, or when because of the particular market situation or low volume of sales in the domestic market of the exporting country, such sales do not permit a proper comparison, the normal value is to be determined on the basis of third country export prices. DSM submits that sales in Switzerland are less than 2% of the total sales of the subject goods

by the company and, therefore, are not representative for determination of normal value. The appropriate market for determination of normal value is the European Union and not Switzerland.

- ii. A number of factors, other than the imports, such as a reduction in customs duty, appreciation of the rupee etc have caused injury to the domestic industry. Injury was also caused by DPCO prices fixed by the Government during the relevant period, which prevented the domestic industry from raising its prices.
- iii. The capacity utilisation has been given for all products and not for subject goods and, therefore, the figures provided are not relevant to the investigations.
- iv. The data for the period during which anti-dumping duties were in force on imports from the EU, should be excluded from the examination, as the imposition of duties led to a sudden reduction in imports, creating a virtual monopoly for the domestic industry. This was a temporary situation and after the duties were removed, competitive imports came into the Indian market from various sources. The information provided does not reflect a natural or potential decline in sales of the domestic industry.
- v. DSM denies that its exports have resulted in price underselling and price undercutting. The sale price of the domestic industry to resellers would naturally be lower than DPCO prices, so as to provide for the expenses and profit margin of the resellers. The average sale price of the domestic industry has to be lower than DPCO prices. Had the sales been made at DPCO prices, there could have been no losses. In view of this factual position, the finding of the Authority, that the landed value of imports from DSM was lower than the sale price of the domestic industry is unjustified, as the landed value of imports is near about the DPCO prices.

- vi. The cost to make and sell of the domestic industry has reduced drastically by almost 50%, whereas the selling price has reduced by about 15%. A marginal decline in prices should not have resulted in significant losses.
- vii. Exports at low prices resulted in heavy losses for the domestic industry. It is unthinkable as to why the domestic industry finds the export prices remunerative, and chooses to increase its exports, whereas, it contends that much higher prices in the local market are causing it injury.
- viii. The productivity of the domestic industry has doubled since 2001-02. These figures are, however, not for the subject goods.
- ix. The observation that the return on capital employed has deteriorated significantly is not supported by figures.
- x. The inventories are not unduly high and not indicative of injury.

Miscellaneous Submissions

- i. The duties are in excess of the injury alleged to have been caused.

A. Submissions by M/s Piramal Healthcare Ltd (earlier known as M/s. Nicholas Piramal India Limited

Submissions concerning scope of Domestic Industry and Standing

- i. M/s Piramal Healthcare Ltd ("M/s Nicolas Piramal India Ltd." as it was known during the original Period of Investigation), the Domestic Industry, had temporarily shut down operations at their plant in Thane, Maharashtra with effect from 30th September 2010 in order to shift the operations to another plant which is now situated at Digwal, Andhra Pradesh with effect from December 2010 and commercial production of the product under consideration has resumed at the new plant. M/s Piramal Healthcare Ltd is obviously qualified as the Domestic Industry for the product under consideration and accounts for complete production of subject goods in India. M/s Piramal Healthcare Ltd. ("M/s Nicolas Piramal India Ltd." as it

was known during the original Period of Investigation) continues to be the sole producer of the subject goods in India.

- ii. Due to the continued and incessant dumping of the subject goods from the subject countries, the Domestic Industry was forced to stop manufacturing from the basic stage and change the manufacturing site and process, in order to effectively compete with the unfair imports from the subject countries.

Submissions relating to confidentiality

- i. The Designated Authority is not liable to provide complete calculations of export price, dumping margin, injury margin etc to DSM as claimed by them. They themselves provided data selectively.
- ii. While allegation of over confidentiality has been raised by DNP, they have not even disclosed the total sales data of Switzerland to the Authority.

Submissions concerning scope of the PUC

- i. Product under consideration has been defined by the Authority as Vitamin A Palmitate, which covers Vitamin A Palmitate 1.7MIU/gm and Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/gm in all its strengths and forms. Hence, the issue of the scope of the Product under consideration and "like articles" has been appropriately decided by the Authority and is not liable for any modification.
- ii. It is denied that Vitamin A Acetate crystals and Vitamin A Palmitate 1.7 are like articles. The crystals are in acetate form and the Domestic Industry is the only domestic manufacturers with the technological know-how and infrastructure to convert Vitamin A crystals into vitamin A Palmitate 1.7.

Submissions relating to Export Price, Normal Value, Dumping Margin and Injury Margin

- i. The dumping margin for the exporters from Switzerland, including DSM, should have been based on the best information available i.e. third country information (European Union) or constructed cost on the basis of price paid or payable in India duly adjusted as prescribed under the Anti-dumping

Rules. Authority has determined normal value and dumping margin for DSM correctly. The allegation of DSM to that extent is false.

- ii. The Designated Authority has not recommended the duties to the extent of the benchmark of DPCO prices, despite the submissions made in this behalf by the Domestic Industry. The Designated Authority has appropriately decided the issue in the Final Findings dated 14th September, 2007 and therefore the allegation of DSM in this regard is liable to be rejected.
- iii. Authority mandates co-operating importers to file a comprehensive Importers Questionnaire Response supported with necessary documentary evidence in this regard. However, no such response appears to be filed by the said reseller within the prescribed time-limits. Hence, accepting the information of the said reseller would amount to unfairly circumventing the established practice. Designated Authority justifiably declined from making any adjustment for the re-sellers profit margin on the DPCO prices.
- iv. The submission that the website of the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) should be relied is wholly irrelevant as the margins referred to therein pertain to formulations and not bulk drugs.
- v. The import data indicates that dumped imports of the subject goods from the subject countries had increased substantially during the injury period.
- vi. The increase in capacity utilization mentioned by DSM is in respect of Vitamin A crystals are due to increase in demand of commercial premixes. Vitamin A crystals are used for captive consumption in manufacture of food & feed premixes. The production of Vitamin A Palmitate 1.7 has not increased significantly during the Period of Investigation.
- vii. The subject goods produced by the domestic industry grew steadily, but fell significantly during the Period of Investigation.
- viii. The domestic sales and total sales of the domestic industry followed a similar trend and after increasing significantly up to 2003-04, declined significantly.

- ix. The dumped imports from the subject countries increased in absolute term as also in relation to imports into India, production in India and consumption in India.
- x. The volume of imports increased more than the increase in demand affecting the market share of the Domestic Industry.
- xi. The dumped prices and consequently the landed price of imports from the subject countries have been lower than the net sales realization and non-injurious price of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting and price underselling.
- xii. The submissions of DSM concerning decline of profits is false and based on mere conjecture. In fact, there have been negligible exports of the Product under consideration as compared to sales in domestic market in the last 5 years. Thus, it is clearly due to the constant pressure on the Domestic Industry as a result of dumped imports, significant losses have been experienced in the domestic sales and have plunged the situation into financial losses from a situation of profits.
- xiii. The number of employees has declined, whereas the wages of the Domestic have significantly increased over the injury period.
- xiv. Due to the financial losses, the cash flow and the return on capital employed also deteriorated considerably during the injury period.
- xv. The allegations made by DSM in its appeal that there is no injury to the Domestic Industry are false, misconceived and unsubstantiated.

Miscellaneous Submissions

- i. The re-adjudicating authority cannot go beyond the remand order and the powers and jurisdiction of lower authority is limited to the extent the case is remanded back. In the instant case, the Designated Authority is restricted from adjudicating any new issues, which are beyond the order of the CESTAT.
- ii. Petitioners did not contest in their appeal before CESTAT on the ground that the Designated Authority, who had heard, did not pass the final finding. All

claims and issues raised by M/s DSM Nutritional relate to the status of M/s Piramal Healthcare as the Domestic Industry.

- iii. Designated Authority has accepted the data of DSM even when they have been non-cooperative throughout the investigation.
- iv. No second hearing before the new Designated Authority is required as none of the parties sought any fresh hearing before the new Designated Authority. Hence, the impugned order of the Hon'ble CESTAT does not apply in the instant case.
- v. DSM could have filed a Mid-Term Review in 2006 when it has been alleged that the Domestic Industry was importing the Vitamin A Acetate crystals. DSM has not filed any such review under Rule 23 of the Rules establishing any such 'change in circumstances' nor has DSM modified its Appeal in this regard.
- vi. Authority should hold DSM "non-co-operative" and rightfully recommend residual duties for DSM in place of the individual margin unfairly granted to DSM.

Comments on the Disclosure statement

16) The comments have been received by the Authority from both domestic industry and M/s DSM. The domestic industry has broadly concurred with the facts as detailed in the disclosure statement. However, M/s DSM have reiterated its earlier submissions with regards to determination of dumping margin, determination of injury margin and non disclosure of some parameters on dumping margin calculations, while accepting the standing of Nicholas Piramal as domestic industry during the POI. The Authority notes that the submissions of the interested parties on all the parameters, to the extent considered relevant, have already been dealt with at appropriate places in these findings. Accordingly, these findings covers the comments of the all the interested parties made in the course of the investigation including the post decisional hearing held by the Authority on 13th December 2011.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 17) The submissions made by the interested parties, to the extent considered relevant, are addressed by the Authority as under:

Scope of Domestic Industry and Standing

- i. As regards submissions by the interested parties on the standing of the domestic industry, the Authority notes that in its final findings dated 14th September 2007, M/s Nicolas Piramal India Ltd. (NPIL), being the sole known producer of the subject goods in India, was considered as domestic industry satisfying the provisions laid down under the Rules. During the entire course of the investigation, none of the interested parties had raised any issue regarding M/s NPIL not being eligible to file the petition.
- ii. The contention by M/s DNP that M/s NPIL have stopped the production of Vitamin-A Palmitate from the basic stage from December 2010 is irrelevant for the present investigation, the same being a post-POI development. Moreover, any change in the process/technology of production of the product under consideration, does not disentitle the domestic producer from the status of 'domestic industry', provided it continues to produce the product under consideration. If the opposite interested parties had to challenge the continued status of the domestic industry, they could have applied for a mid-term review, substantiating the changed circumstances with adequate documentary support. The Authority notes that the period of investigation in the subject investigation was from 1st April 2004 to 30th September 2005 (18 months period). Therefore, any subsequent developments with regard to the changes in the manufacturing process and/ or continuation or discontinuation of manufacturing of the subject goods by the domestic industry, are not relevant to the scope of the present remand proceedings. In case there is any change in the structure of domestic industry, post-POI, the interested

parties can still seek review for the changed circumstances, if any, in terms of the relevant provisions of the Anti-Dumping Rules. In view of the above, the Authority reaffirms the standing of M/s Piramal Healthcare Ltd ("M/s Nicolas Piramal India Ltd." as it was known during the original Period of Investigation) as the domestic industry, within the meaning of the Rules.

- iii. On the one hand, the opposite interested parties argue that Vitamin A Palmitate and Vitamin A Acetate are like articles and at the same time allege that Nicholas Piramal is not a domestic industry as they are presently engaged in converting Vitamin A Acetate in to Vitamin A Palmitate. The Authority notes that when an intermediate input is converted in to a final product, through a chemical process, the process of conversion does constitute manufacturing and the two cannot constitute like articles. Moreover, change in the route/technology/process of production does not disentitle a domestic producer from the status of domestic industry, as long as it is engaged in the production and supply of the subject goods.

Export price, normal value, dumping margin:

- iv. The Authority notes that the petitioners before the Hon'ble CESTAT M/s DNP have primarily contested the determination of normal value based on the domestic sales in Switzerland, which are stated to be less than 2% of the total sales of the subject goods and hence, not representative for determination of the normal value. M/s DNP have also contested that some of its claims with regard to the level of trade, sales based on different levels of order quantities etc were not considered by the Authority in its findings dated 14th September 2007. However, no additional information supported by documentary evidence has been furnished by M/s DNP to substantiate its claim in this regard.
- v. While examining the submissions of the interested parties, the Authority in the final findings dated 14th September 2007 had observed as under:

"59. The Authority notes that the exporter sold *** Kg of Vitamin A palmitate 1.7 MIU/Gm and *** kgs of 1.0 MIU/Gm in the home market during the POI against export of *** kgs of 1.7 MIU/Gm to India during the same period. Therefore, home market sales of the like product constituted more than 5% of the sales to India. Such home market sales being in sufficient quantities as per the Agreement are therefore, required to be considered for the purpose of determination of Normal value and accordingly, the Authority has considered the same for determination of normal value in the exporting country.

60. The exporter, however, made a plea that if their home market sales are required to be considered for the purpose of determination of normal value due consideration has to be made towards the difference in sales quantities and level of trade as the domestic sales are in smaller quantities and to direct retail customers and therefore, not comparable with the export sales transactions. The exporter, vide letter dated 10th April 2007, was asked to quantify and demonstrate the level of trade adjustments and other factors that affect the price comparability as claimed by them for fair comparison. The exporter, vide its letter dated 24th April and 16th May 2007 provided certain information and arguments for quantification of the adjustments towards the factors affecting price comparability and direct selling expenses in respect of domestic sales on account of small quantity sales to direct customers in Switzerland.

61. The Authority notes that Rule 6(i) in Annexure I and Article 2.4 of the Agreement provide that "due allowance shall be made in each case, on its merit, for differences which affect price comparability, including difference in conditions and terms of trade, taxation, level of trade, quantities, physical characteristics, and other differences which are also demonstrated to affect price comparability". In terms of the above

provisions the claims of the exporter has been examined by the Authority as follows:

- a) *The claim of the exporter on adjustments towards lower transaction volumes in domestic market has been examined. It has been claimed that the domestic sales are in small quantities and average quantity sold per transaction in the domestic market is 41 Kgs whereas average quantity per sale in the Indian market is about 416 Kg. It has been argued that the difference in order quantities affects the respective prices as they charge a minimum quantity surcharge on small order quantities. In support of this some export invoices with small quantities have been produced. However, no evidence of small order surcharge in domestic market has been provided. It has been further argued that the quantities have direct impact on the price and an adjustment has to be made for comparison purpose. Accordingly, the exporter has quantified the adjustment based on the difference in unit price for sales transactions to India of quantity below 300 Kg and above 300 kg. However, these quantity difference and small quantity surcharges are with reference to the export sales and no evidence of such a variation in prices on account of quantities in the home market has been provided. Therefore, the Authority is of the view that such adjustment cannot be admitted.*
- b) *In addition to the adjustment towards quantities, the exporter has claimed level of trade adjustment on the grounds that the domestic sales are mostly to direct consumers, whereas the export sales to India are mostly to resellers, which also affects price comparability. It has been argued that the price to direct customers in Switzerland and European markets is generally higher by about 5 to 7% than the prices to resellers. In support of this claim they have produced the evidence of contemporary invoices of same products to direct customers and*

reseller in Swiss market, which indicates a difference of about 5% between these prices. It has been argued that this mark up is allowed to the reseller to take care of its expenses and profit. Usually, resellers or agent gets a commission; or a markup in its prices which takes into consideration its expenses and margins and a commission/margin of 3% to 5% is normal in the trade. Therefore, the Authority is of the view that an adjustment of 3% towards this may be justified.

- c) The exporter has also claimed adjustments towards direct selling expenses in the home market i.e., inland freight from the plant to warehouse and associated insurance, storage and handling expenses, freight from warehouse to customer and associated insurance expenses. As far as domestic freight from warehouse to domestic customers are concerned, the exporter has provided the evidence of actual cost incurred for delivery through DHL courier and accordingly, the revised freight cost has been worked out as US *** per Kg.

62. Accordingly, the Normal value in Switzerland at ex-works level for the product under consideration works out as follows:

Represent ative sales in Home Market	Qty in Kg	Price in Euro	Price in US\$	Exch Rate	Adjust ments US\$/K g	Normal Value US\$/K g
VIT A PALM 1.7 BHA/BHT	***	***	***	***	***	***
VIT A PALM 1.7 TOCO	***	***	***	***	***	***

b) Export Price and Dumping Margins

i) DSM Nutritional products

63. DNP has reported *** Kgs of export sales of the subject goods to India during the POI covering Vitamin A Palmitate 1.7 BHA/BHT and 1.7

64. The exporter has provided information for adjustments towards direct selling expenses on account of Inland Freight from the Sisseln site to Venlo, Netherlands (warehouse) and associated insurance expenses; storage and handling charges; overseas freight from Switzerland to Singapore and Singapore to India and associated insurance expenses; and shipping charges. No adjustment has been claimed on packing expenses as the same is included in the cost and there is no difference between the export packing and domestic packing. Accordingly, the net export price at ex-works level works out as follows:

[illegible]

VIT A PALM 1.7 TOCO	***	***	***	***	***	***	***
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

65. On the basis of Normal value determined for Switzerland and net export price determined for DNP, dumping margin for this cooperating exporter has been assessed as follows:

	NV US\$/Kg	Qty Kg	EP US\$/Kg	Qty Kg	DM US\$/Kg	DM value
VIT A PALM 1.7 BHA/BHT	***	***	***	***	***	***
VIT A PALM 1.7 TOCO	***	***	***	***	***	***
Weighted Average		***	***	***	***	***

66. DSM, in its post disclosure submissions has argued that since the Indian law does not provide for a threshold limit for the domestic sales to be treated as in sufficient quantities for determination of normal value the Authority should not merely relied on the WTO Agreement in this respect and evaluated the matter on its own merit in view of the fact that the domestic sales in Switzerland was very small (less than 2%) compared to its total sales. It has also been argued that a particular market situation i.e., the sales in Switzerland, have been made in very small quantities whereas sales for exports to India are in much larger quantities in Switzerland, which should have been taken into account for determination of normal value in

Switzerland. Under the above circumstances appropriate market for determination of normal value is the European Union and not Switzerland. The exporter has also commented that the weighted average dumping margin should be worked out on the basis of weighted average normal value and weighted average export price.

67. Domestic industry, in its post disclosure submissions, has argued that, without conducting the on-site verification, acceptance of the data and other claims made by DSM is unwarranted and unsubstantiated. Domestic industry has further argued that under the above circumstance dumping margin for the exporters from Switzerland, including DSM should have been based on the best information available i.e. third country information (European Union) or constructed cost on the basis of price paid or payable in India duly adjusted as prescribed under the Rules.

68. In this connection the Authority notes that the sales in Swiss market were found to be in sufficient quantities in relation to the exports to India, (which constituted more than 20% of sales to India) and therefore, considered appropriate for comparison with the exports to India. However, the exporters claimed certain adjustment on its home market prices towards certain factors that affected the price comparability and such adjustments, which could be demonstrated and justified by the exporter with evidence, have been accepted by the Authority. The claim for adjustment on account of a minimum quantity surcharge could not be demonstrated by the exporter with reference to domestic sales and therefore, has not been accepted. Therefore, the arguments of the exporter in this regard are not tenable. As far as the error in dumping margin calculation is concerned, Dumping Margin is determined as the weighted average of the intermediate dumping margins, determined at subtype levels (weighted on the export quantities of product subtypes). The dumping margin has been determined for the above exporter correctly on the above basis. Therefore, there is no need for any change of dumping margins."

18) The Authority notes that all the submissions of M/s DNP, as regards determination of normal value, export price and dumping margin are concerned, to the extent considered relevant by the Authority and duly substantiated by the interested parties, were examined and addressed by the Authority in its final findings dated 14th September 2007. In view of the above the Authority reaffirms the normal value, export price and dumping margin determined in respect of M/s DNP, Switzerland in the final findings issued by the Authority.

Injury and Causal Link

19) It has been argued by M/s DNP that the injury has been caused to the domestic industry due to the subject goods being controlled by the Government under Drug Price Control Order (DPCO). The Authority notes that any injury to the domestic industry for the reasons other than the dumped imports needs to be assessed and segregated. In this regard the Authority in its final findings, dated 14th September 2007 noted as under:

*"131. The Authority also notes that in the instant case the NIP has been determined based on the data for the period of investigation as per the consistent practice of the Authority. The NIP has been determined as Rs *** per Kg of Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/Gm. The current DPCO price fixed by NPPA is Rs4564.50 per Kg with effect from 27.03.2007, supposed to have been fixed on the basis of cost data for the period 2005-2006. There is a significant difference in the period for which data has been examined by the Authority, i.e., 18 months from 1st April 2004 to 30th September 2005, against 12 months data supposed to have been examined by NPPA for April 2005-March 2006. Further apparently, the rate of return adopted by NPPA and the Authority are different. Therefore, it would not be appropriate to adopt NPPA current price under DPCO for injury margin determination. By the same logic the NPPA price for the earlier period would also not be appropriate to determine the injury margin in this case.*

Therefore, the Authority has compared the NIP determined as above with the landed value of imports to work out the injury margins.

132. However, the Authority notes that during the injury investigation period the DPCO ceiling price had set the maximum price at which the domestic industry could have sold the goods in the domestic market. Therefore, as per the non-attribution standards, any injury, which could have been caused to the domestic industry due to this ceiling price, cannot be attributed to the dumped imports and the injury margin of the dumped imports needs to be restricted to the extent to which the dumped imports were below the DPCO price prevalent during the investigation period. Accordingly, the injury margin that can be attributed to the dumped imports work out as under:"

Country	Exporter	NIP	LV	DPCO Price during POI	Injury Margin	Injury attributed to dumped imports	Injury attributed to dumped imports
		Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	%
Switzerland	DSM Nutritional Products	***	***	4125.9	***	***	5-15%
Switzerland	All Others	***	***	4125.9	***	***	15-25%
China PR	NHU with Synchem	***	***	4125.9	***	***	10-20%
China PR	All others	***	***	4125.9	***	***	25-35%

20) The analysis as above clearly demonstrates that the submissions of M/s DNP with regard to injury on account of DPCO controlled prices were duly

addressed and considered by the Authority in the final findings issued on 14th September, 2007.

- 21) The Authority in its final findings dated 14th September 2007 further observed as under:

"120. As far as the arguments of the interested parties that injury caused to the domestic industry is on account of the Government's pricing and tax policies and has nothing to do with the dumped imports, the Authority notes that the landed value of the imports from the subject countries are much less than the DPCO price, even if a reasonable margin for the resellers is considered, indicating thereby that even if DPCO price is taken as the bench mark the dumped import have significant injurious effect on the domestic industry. Therefore, the arguments of the exporters that the Govt. Policies and DPCO prices are sole cause of injury are not valid."

- 22) In view of the above, the Authority notes that the submissions made by DNP that the injury has been caused to the domestic industry due to the subject goods being controlled by the Government under Drug Price Control Order (DPCO) and not due to the dumped imports, are unfounded and baseless.

- 23) As regards the submissions by M/s DNP for the sales price to the resellers being lower than the DPCO prices in order to provide for profit margins and the expenses of the sellers, the Authority in its final findings dated 14th September 2007 noted as under:

"129. The interested parties have argued that since DPCO price is the maximum price for sale in India this price should be taken into account for determination of injury if any caused to the domestic industry and injury caused to the domestic industry due to the DPCO price during the injury investigation period should not be attributed to the dumped imports. It has been further argued that the DPCO price being the maximum price for sales in India the comparison should take into account a margin for

reseller's profit. In support of this some additional information of reseller has been produced by the interested parties after disclosure which could not be taken on record for the reasons stated earlier.

- 24) Although, the submissions regarding adjustment of resellers margin was made by M/s DNP post disclosure, nevertheless the same has already been addressed by the Authority in the final findings dated 14th Sep. 2007 as under:

"130. The Authority notes that the export transactions of these exporters are to direct customers as well as resellers. The importers have not provided any information about their reselling price and SGA expenses incurred or profit earned by them on such imports. Therefore, the Authority does not find any justification to make such allowance for the reseller's profit margin on the DPCO prices for comparison purpose and determination of injury margin."

- 25) M/s DNP, Switzerland has also reiterated submissions on other aspects of injury analysis, which inter-alia includes capacity utilization, reduction in custom duty, export price being lower than domestic selling price, productivity of the domestic industry, returns on capital employed etc. The Authority notes that the submissions of the interested parties to the extent considered relevant by the Authority, have already been addressed by the Authority in its final findings dated 14th September 2007. The Authority in its conclusions on the injury to the domestic industry noted as under in the final findings dated 14th September 2007:

"G.3.4 Overall assessment

115. The above analysis of the factors shows that in spite of the good demand in the domestic market, improvement in productivity and reduction in its cost of production compared to the previous years, the industry

suffers injury on account of decline in production, and sales; low net sales realization; higher inventory built up; negative or low return on investments and profits. The injury suffered is material and significant. Therefore, the arguments of the interested parties that the petitioner domestic industry does not suffer any material injury are not valid."

Confidentiality

- 26) As regards the submission by M/s DNP that the information on the workings of dumping margin and the injury margin calculation has not been disclosed to them by the Authority, the Authority notes that the calculation of injury margin is based on the NIP of the domestic industry and therefore being confidential in nature, cannot be disclosed. As far as information on the workings of dumping margin is concerned, M/s DNP in their comments dated 31st August, 2007 on the disclosure statement issued by the Authority, stated as under:

"We further submit that there appears to be a calculation error in the dumping margin. The average weighted normal value as per figure provided should be ***, and the weighted export price should be ***.

This would give a dumping margin of ***."

The above stated comments of M/s DNP imply that they were very much aware of the required information.

Miscellaneous Submissions

- 27) As regards the submission of M/s DNP that the duties imposed are in excess of the injury alleged to have been caused, the Authority notes that the duties recommended by the Authority in its final findings dated 14th September, 2007, are lesser of the margins of dumping and injury and thereby reasonable as per the Rules.

Conclusion and Recommendation

28) After examining and addressing the submissions made by the interested parties pursuant to the post decisional hearing held by the Authority, in compliance with the orders dated 11th August 2011 by the Hon'ble CESTAT, the Authority notes that no modification is warranted in the final findings issued by the Authority vide Notification No.14/11/2005-DGAD dated 14th September, 2007. The Authority, therefore, hereby re-affirms its findings made vide Notification No. 14/11/2005-DGAD dated 14th September, 2007 and the recommendations made therein.

VJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority